

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RAJYA SABHA STARRED QUESTION No. 331 TO BE ANSWERED ON 04th April, 2022

Biofuel Policy 2018

*331 SHRI IRANNA KADADI:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

- (a) whether Government has introduced the new Biofuel Policy in 2018;
- (b) the details of the Letters of Intent obtained in furtherance of the Policy to manufacture biofuels, categorised by type of biofuel;
- (c) whether the country is on track to achieve target of ethanol blended petrol as mentioned in the Biofuel Policy, 2018 and, if not, the details thereof;
- (d) the details of the budget allocated for implementing the Biofuel Policy, 2018 and the amount expended till now, State-wise; and
- (e) whether the rules to be formulated under the policy are in the final stages of drafting and, if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF PETROLEUM & NATURAL GAS (SHRI HARDEEP SINGH PURI)

(a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (e) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION No. 331 TO BE ANSWERED ON 04.04.2022 REGARDING BIOFUEL POLICY 2018 ASKED BY SHRI IRANNA KADADI.

- (a) Government has notified the National Policy on Biofuels-2018 on 4th June 2018. The Government is promoting biofuels with the broader objectives of reducing import dependency, generating employment, providing better remuneration to farmers, promoting better waste management practices, etc.
- (b) Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) float annual tender for ethanol procurement under the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme. For the ongoing Ethanol Supply Year (ESY) 2021-22, OMCs tendered a requirement of 459 crore litres and based on the offers received, OMCs have released Letter of Intents (LoIs) for procurement of 416.33 crore litres of ethanol as on 27.03.2022.

OMCs have also floated Expression of Interests (EoI) to shortlist interested bidders who wish to enter into Long-term Off-take Agreement for supply of ethanol in the deficit States from upcoming dedicated ethanol plants.

Used Cooking Oil (UCO) has been identified as a potential raw material for biodiesel production and public sector OMCs have floated EoIs for procurement of Biodiesel produced from UCO across 300 locations. OMCs have received offers for setting up 61 plants with a production capacity of approximately 36 crore litres per annum for manufacturing Biodiesel from UCO.

With a view to promote the use of Compressed Bio Gas (CBG) as automotive fuel, Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT) initiative has been launched on 01.10.2018 under which OMCs have been inviting EoI from potential entrepreneurs to produce CBG. SATAT initiative envisages for establishment of 5000 CBG plants across the country with an estimated production of 15 MMT CBG per annum by 2023-24. Till 28.2.2022, Oil PSUs have released LoIs for establishment of 3160 CBG plants for procurement of CBG.

(c) The National Policy on Biofuels-2018 provides an indicative target of 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of Biodiesel in diesel by 2030. The Government has advanced the target of 20% blending of ethanol in petrol to 2025-2026. For the ongoing Ethanol Supply Year (ESY: 2021-22), OMCs have already achieved 9.6% blending as on 27th March, 2022.

- (d): In March, 2019, Government has notified the "Pradhan Mantri JI-VAN (Jaiv Indhan- Vatavaran Anukool fasal awashesh Nivaran) Yojana" for providing financial support to integrated bio-ethanol projects for setting up second generation ethanol projects in the country using lignocellulosic biomass and other renewable feedstock. The total financial outlay for the scheme is Rs. 1969.50 crore for the period 2018-19 to 2023-24. Financial assistance of Rs. 150 crore each to the four bio-ethanol projects and Rs. 15 crore to one demonstration project being set up by Oil CPSEs have been approved under the PM JI-VAN Yojana.
- (e): The biofuel policy comprehensively covers various aspects of biofuel program including strategy and approach, interventions and enabling mechanism, role of stake holders, institutional mechanism, international cooperation, etc. Pursuant to this policy, relevant procedures and processes have been put in place.

भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या: 331 दिनांक 04 अप्रैल, 2022

जैव ईंधन नीति, 2018

331. श्री इरण्ण कडाडि:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार ने 2018 में नई जैव ईंधन नीति पेश की है;
- (ख) जैव ईंधन के प्रकार द्वारा वर्गीकृत जैव ईंधनों के निर्माण की नीति को आगे बढ़ाने के संबंध में प्राप्त किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, जैसा कि जैव ईंधन नीति, 2018 में उल्लेख किया गया है, और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) जैव ईंधन नीति, 2018 को लागू करने के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है तथा अब तक व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (इ.) क्या इस नीति के अधीन बनाए जाने वाले नियम प्रारूपण के अंतिम चरण में हैं और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'जैव ईंधन नीति, 2018' के संबंध में संसद सदस्य श्री इरण्ण कडाडि द्वारा दिनांक 04.04.2022 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 331 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

- (क) सरकार ने दिनांक 04 जून, 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 अधिसूचित की है। सरकार आयात निर्भरता में कमी करने, रोजगार का सृजन करने, किसानों को अपेक्षाकृत अधिक पारिश्रमिक प्रदान करने और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य से जैव ईंधनों को बढ़ावा दे रही है।
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंम नियां (ओएमसीज़) एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए वार्षिक निविदा आमंत्रित करती हैं। चल रहे एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2021-22 के लिए ओएमसीज़ ने 459 करोड़ लीटर की आवश्यकता के लिए निविदा जारी की है और प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर ओएमसीज़ ने दिनांक 27.03.2022 की स्थिति के अनुसार 416.33 करोड़ लीटर एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए आशय पत्र (एलओआईज) जारी किए हैं।

ओएमसीज़ ने आगामी समर्पित एथेनॉल संयंत्रों से एथेनॉल की कमी वाले राज्यों में एथेनॉल की आपूर्ति हेतु ऐसे इच्छुक बोलीदाताओं के चयन के लिए रुच की अभिव्यक्ति (ईओआई) भी आमंत्रित की है जो दीर्घकालिक ऑफटेक करार करना चाहते हैं।

जैव डीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त खाद्य तेल (यूसीओ) की पहचान भावी कच्चे माल के तौर पर की गई है और सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ ने 300 स्थलों पर यूसीओ से उत्पादित जैव डीजल की अधिप्राप्ति के लिए ईओआईज आमंत्रित की हैं। ओएमसीज़ को यूसीओ से जैव डीजल के विनिर्माण हेतु लगभग 36 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाले 61 संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2018 को किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल शुरू की गई है जिसके तहत ओएमसीज़ सीबीजी के उत्पादन हेतु भावी उद्यमियों से ईओआई आमंत्रित करती रही हैं। सतत पहल में वर्ष 2023-24 तक 15 एमएमटी सीबीजी प्रतिवर्ष के अनुमानित उत्पादन के साथ पूरे देश में 5000 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। दिनांक 28.02.2022 तक तेल पीएसयूज़ ने सीबीजी की अधिप्राप्ति हेतु 3160 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए एलओआईज़ जारी की है।

- (ग) राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल का मिश्रण करने और डीजल में 5 प्रतिशत जैव डीजल का मिश्रण करने का सांकेतिक लक्ष्य दिया गया है। सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की समय-सीमा कम करके वर्ष 2025-2026 कर दी है। चल रहे एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई: 2021-22) के लिए ओएमसीज़ दिनांक 27 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 9.6 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुकी है।
- (घ) मार्च, 2019 में सरकार ने देश में लि नोसेल्यूलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फ डस्टॉक का इस्तेमाल करने वाली दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना हेतु एकीकृत एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने के लिए "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" को अधिसूचित किया है। योजना के लिए वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक की अवधि हेतु कुल वित्तीय परिव्यय 1969.50 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जी-वन योजना के तहत तेल सीपीएसईज द्वारा स्थापित की जा रही चार जैव-एथेनॉल परियोजनाओं में से प्रत्येक को 150 करोड़ रुपए और एक प्रदर्शन संयंत्र को 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता अनुमोदित कर दी गई है।
- (इ.) जैव ईंधन नीति में कार्य नीति और दृष्टिकोण, उपायों तथा समर्थकारी व्यवस्था, पणधारकों की भूमिका, संस्थागत व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय सहयोग आदि सहित जैव ईंधन कार्यक्रम के विभि न पहलुओं को व्यापक तौर से शामिल किया गया है। इस नीति के अनुसरण में संबंधित पद्धतियों और प्रक्रियाओं को लागू कर दिया गया है।

* * *

श्री इरण्ण कडािड: सर, सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 को अधिसूचित किया है, ...(व्यवधान)... लेकिन पिछले चार वर्षों में इस निधि को ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please do not come inside the Well. ... (Interruptions)... Please do not come inside the Well. ... (Interruptions)...

श्री इरण्ण कडािड : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैव ईंधन क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please put your question in brief. ...(Interruptions)...

श्री इरण्ण कडािड : सरकार इस निधि को कब तक शुरू करेगी? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : कडाडि जी, आप प्रश्न फिर से पूछें। ...(व्यवधान)... It was not audible. माननीय मंत्री जी, आप कृपया उनका प्रश्न सुनें। ...(व्यवधान)...

श्री इरण्ण कडािड : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अंतर्गत ...(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): That is not the way. ...(Interruptions)... That is not the way. ...(Interruptions)... Hon. Member, please do not come into the Well. ...(Interruptions)... Please go back to your seats. ...(Interruptions)...

श्री इरण्ण कडािड : सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अंतर्गत ...(व्यवधान)... निधि का प्रावधान किया है, ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): That is not the way. ... (Interruptions)... That is not the way. ... (Interruptions)...

श्री इरण्ण कडािड : लेकिन पिछले चार वर्षों में इस निधि को ...(व्यवधान)... नहीं दिया गया है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He is asking an important question. ...(Interruptions)... He is asking an important question. ...(Interruptions)... Please

do not come into the Well. ...(Interruptions)... That is not the way. ...(Interruptions)...

श्री इरण्ण कडािड : मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जैव ईंधन क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार इस निधि को कब तक शुरू करेगी? ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, hon. Minister to reply. ...(Interruptions)... Please do not come into the Well. ...(Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the policy which was commenced in 2018 achieves certain additionalities (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): This is not the way. ...(Interruptions)... This is not the way. ...(Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, it may be recalled that up to the year 2014... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, please go back to your seats. ...(Interruptions)... This is not the way. ...(Interruptions)... This is not the way. ...(Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: All the steps taken after 2014 resulted in... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We are having an important discussion. ... (Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Ethanol blending and ethanol being available for blending up to ...(Interruptions)... 1.4 per cent ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Minister, kindly reply in brief. ...(Interruptions)... Briefly, please.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Today, Sir, that percentage has gone up to 9.6 per cent ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please go back to your seats. ... (Interruptions)... Question Hour is going on. ... (Interruptions)... Question Hour is going on. ... (Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Target of 20 per cent blending is being advanced to 2025, and, we have been able to do this....(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): This is not the way. ...(Interruptions)... This is not the way. ...(Interruptions)... Please go back to your seats. ...(Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Earlier, it was limited to(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Question Hour is going on. ...(Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Now, with regard to the ethanol plan... (Interruptions)... We have introduced sugar, juice, maize, rice... (Interruptions)... Cellulosic ethanol production.... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Kindly conclude, hon. Minister. ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Second supplementary. ...(Interruptions)... Please question briefly.

श्री इरण्ण कडािड : मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार वर्तमान में ...(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Question Hour is going on. ...(Interruptions)...

श्री इरण्ण कडािड : विकसित करने के लिए कोई योजना निर्धारित कर रही है? ...(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Minister. ... (Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, last year, we were able to introduce ethanol blending up to about 300 crores litres per year ... (Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please go back to your seats. I will allow the Leader of the Opposition. ...(Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: As a result of the steps that we have taken, ethanol blending this year is expected to be around 450 crore litre and we plan to progressively scale it up so that we can achieve the expected ethanol blending.... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, please go back to your seats. ...(Interruptions)... I will allow the Leader of the Opposition. ...(Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, with regard to the target ...(Interruptions)...

Around 1,000 crore litre per year ...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The House is adjourned till 2.00 p.m.